



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226280
CG-DL-E-31032021-226280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 111]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

मामला सं. एडी (एसएसआर)-06/2021

विषय : चीन जन.गण., जापान, कोरिया आर.पी. एवं यूक्रेन के मूल से अथवा वहाँ से आयातित "सभी प्रकार की चौड़ाई और मोटाई वाले, क्लेड प्लेटिड या कोटिड नहीं, आयरन या नॉन अलाय स्टील या अन्य अलॉय स्टील के कोल्ड रोलड/कोल्ड रिड्यूस्ड फ्लैट स्टील उत्पादों" के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/6/2021-डीजीटीआर.— 1. इंडियन स्टील एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., जापान, कोरिया आर.पी., और यूक्रेन (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सभी प्रकार की चौड़ाई और मोटाई वाले क्लेड प्लेटिड या कोटिड नहीं, आयरन या नॉन अलाय स्टील या अन्य अलॉय स्टील के कोल्ड रोलड/कोल्ड रिड्यूस्ड फ्लैट स्टील उत्पादों" के संबंध में (जिसे आगे "संबद्ध वस्तुएं" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं

की पहचान, आकलन तथा पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू स्टील कोटिड प्रोडक्ट लि. और आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक उत्पादक” भी कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। घरेलू उत्पादकों अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू स्टील कोटिड प्रोडक्ट लि. और आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक उत्पादक” भी कहा गया है) ने आवेदन में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाने के पश्चात भी संबद्ध देशों से पाटन जारी है और शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने/पुनरावृत्ति और क्षति की संभावना है। आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 11 अप्रैल, 2016 को आरंभ की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 3 अगस्त, 2016 की प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार अंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 45/2016-सीमाशुल्क के अनुसार लागू किया गया था। विस्तृत जांच के अनुसरण में प्राधिकारी ने, अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/12/2016-डीजीएडी दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को 12 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 18/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 16 अगस्त, 2021 तक लागू रहेंगे।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सभी प्रकार की चौड़ाई और मोटाई वाले क्लेड प्लेटिड या कोटिड नहीं, आयरन या नॉन अलाय स्टील या अन्य अलाय स्टील के कोल्ड रोलड/कोल्ड रिज्यूड फ्लैट स्टील उत्पाद” हैं।

निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया है :-

- (क) स्टेनलैस स्टील।
- (ख) हाई स्पीड स्टील अर्थात् 7 प्रतिशत या अधिक भारांश के 0.6 प्रतिशत या अधिक कार्बन और 3 से 6 प्रतिशत क्रोमियम की संयुक्त मात्रा के साथ तीन में से कम से कम 2 तत्वों, मोलीबडीनम (एम ओ), तंगस्टन (डब्ल्यू) और वनाडियम (वी) पर, अन्य तत्वों के साथ या उसके बिना, अंतर्निहित करने वाला अलाय स्टील।
- (ग) ग्रेन ओरिएंटेड और नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की पुष्टि करने वाले सिलिकॉन इलैक्ट्रिकल स्टील अर्थात् अलाय स्टील जिसमें भारांश द्वारा न्यूनतम 0.6 प्रतिशत किंतु सिलिकॉन का अधिकतम 6 प्रतिशत और कार्बन का अधिकतम 0.08 प्रतिशत शामिल हो। इस स्टील में भारांश द्वारा अधिकतम 1 प्रतिशत एल्यूमीनियम भी शामिल हो सकता है किंतु, कोई अन्य तत्व ऐसे समानुपात में नहीं होगा जो स्टील को अन्य अलाय स्टील की विशेषताएं दे सके।
5. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।
6. पीयूसी में कॉयल्स या कॉयल्स के बिना कोल्ड रोलड/कोल्ड रिज्यूड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं जिसमें स्लिट कॉयल या शीट, ब्लैंक चाहे वे अनील्ड या बॉक्स अनील्ड या बैंच अनील्ड या सतत अनील्ड या किसी अन्य एनीलिंग प्रक्रिया या पूर्ण हार्ड या आंशिक रूप से हार्ड हो या नहीं, शामिल हैं। संबंधित उत्पाद में कोल्ड

रोलड/कोल्ड रिड्यूज्ड फ्लैट स्टील उत्पाद, जो प्राइम या नॉन प्राइम क्वालिटी के अनुरूप हैं चाहे वे 4-हाई रिवर्सिबल मिल, 6 हाई रिवर्सिबल मिल, सेंडजिमिर मिल, 20- हाई कोल्ड रोलिंग मिल, पिकलिंग लाइन्स से रोलड हो या नहीं और टेंडम कोल्ड रोलिंग मिल्स (पी एल टी सी एम), सतत अनीलिंग लाइन (सीएएल) या कोई अन्य कोल्ड रोलिंग कोल्ड रिड्यूसिंग प्रक्रिया शामिल है। ये उत्पाद किसी प्रकार के, मानक, विशेष विवरण और ग्रेड के आयलड या आयलड के बिना आपूर्ति किए गए हो सकते हैं। ये उत्पाद स्टील की विभिन्न गुणवत्ताओं के अनुरूप हो सकते हैं जिनमें पूर्णतः हार्ड, आंशिक रूप से हार्ड, व्यापारिक क्वालिटी, ड्राइंग, डीप ड्राइंग, एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग, इंटरस्टीशियल फ्री स्टील, हार्ड स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील, एडवांस हार्ड स्ट्रेंथ स्टील, अल्ट्रा हार्ड स्ट्रेंथ स्टील, अलॉय स्टील, माइक्रो अलॉय स्टील, स्ट्रिप स्टील (ट्रांसफार्मेशन इंडसूस्ड प्लास्टीसिटी), टिन मिल ब्लैक प्लेट्स (टीएमबीपी) और किसी वैक्यूम डिगैसिंग प्रक्रिया के जरिए वैक्यूम की गई या न की गई बहुत सी अन्य योग्यताएं, शामिल हैं किंतु उन तक सीमित नहीं हैं। ये स्टील स्किन पास/टेंपर रोलिंग के साथ या उसके बिना, एल्यूमिनियम किल्ड के साथ अथवा उसके बिना नान एजिंग क्वालिटी बोरोन को अंतर्निहित करके या उसके बिना और/या टिटैनियम और/या वेनेडियम अथवा भार द्वारा किसी स्तर के किसी अन्य उपयुक्त तत्वों के साथ उत्पादित और आपूर्ति की जा सकती है।

7. इन स्टीलस् के बहुत से विभिन्न अंतिम प्रयोग प्रयोज्य हो सकते हैं इनमें ये शामिल हैं किंतु ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ट्रैक्टर्स, बाईसिकल, अप्लाइसिंस, फर्नीचर, इलैक्ट्रिकल पैनल्स, पैकेजिंग ड्रम्स, बैरल्स, जनरल इंजीनियरिंग, के लिए सबसेटेंट कलर कोटिंग गाल्वेनाइजिंग, मेटल कोटिंग/प्लेटिंग, टिन प्लेट आदि और बहुत से अधिक प्रयोजनों तक सीमित नहीं हैं।
8. पीएमसी को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष शीर्ष 7209, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह वर्तमान समीक्षा जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
9. यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा याचिका में पीसीएन कार्य प्रणाली का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, यह नोट किया गया है कि मूल जांच में, घरेलू उद्योग द्वारा पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव किया गया था और प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का निर्धारण किया था। मूल जांच में निर्धारित पी सी एन नीचे दिए गए हैं और इसका वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए प्रस्ताव किया गया है।

| क्र.सं. | अंकों की संख्या | विवरण | कोड |
|---------|-----------------|---|-------|
| 1 | 1 | सीआरएफएच – कोल्ड रोलड पूर्णतः हार्ड, आंशिक रूप से हार्ड सहित | च |
| | | अनीलड - कोल्ड रोलड अनीलड | क |
| 2 | 1 | "कॉयल" स्लिट कॉयल सहित | भ |
| | | विभिन्न आकारों और आकृति के शीटों और ब्लैक सहित "नॉट-इन-कॉयल" | म |
| 3 | 1 | अलॉय | ठ |
| | | नॉन अलॉय | ड |
| 4 | 4 | कार्बन सहित प्लेन कार्बन स्टील $\leq 0.15\%$ एवं अधिकतम यूटीएस ≤ 410 एमपीए – के अनुरूप: क. व्यापारिक क्वालिटी; ख. ड्राइंग / डीप ड्राइंग क्वालिटी (डी/डीडी) | थ 01थ |

| क्र.सं. | अंकों की संख्या | विवरण | कोड |
|---------|-----------------|--|--------|
| | | ग. एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी (ईडीडी) | |
| | | कार्बन सहित प्लेन कार्बन स्टील $\leq 0.06\%$ एवं अधिकतम यूटीएस ≤ 350 एमपीए - के अनुरूप इंटरस्टीशियल फ्री - एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी (आई एफ-ईडीडी) | थ 02 थ |
| | | प्लेन कार्बन हाई स्ट्रेंथ स्टील्स यूटीएस के साथ इंटर स्टीशियल युक्त अथवा नहीं ≥ 350 एमपीए - आईएफ-एचएस अथवा एचएस | थ 03 थ |
| | | एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी (एएचएसएस) प्लेन कार्बन और/अथवा माइक्रो अलॉय स्टील न्यूनतम यूटीएस सहित ≥ 440 एमपीए | थ 04 थ |
| | | न्यूनतम यूटीएस के साथ एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी (एएचएसएस) का माइक्रो-अलॉयड स्टील ≥ 590 एमपीए | थ 05 थ |
| | | न्यूनतम यूटीएस के साथ एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी (एएचएसएस) का माइक्रो-अलॉयड स्टील ≥ 780 एमपीए | थ 06 थ |
| | | न्यूनतम यूटीएस के साथ एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी (एएचएसएस) का माइक्रो-अलॉयड स्टील ≥ 980 एमपीए | थ 07 थ |
| | | न्यूनतम यूटीएस के साथ बैक हार्डनिंग स्टील ≥ 370 एमपीए (बीएच) | थ 08 थ |
| | | न्यूनतम यूटीएस के साथ दोहरे फेज वाला स्टील ≥ 370 एमपीए (डीपी) | थ 09 थ |
| | | कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील (सीओआरटीईएन) | थ 10 थ |
| | | कार्बन सहित मध्यम और हाई कार्बन स्टील $>0.15\%$ | थ 11 थ |
| | | कोई अन्य ग्रेड/क्वालिटी | थ 12 थ |
| 5 | 1 | ≤ 0.50 मि.मि. | छ |
| | | $> 0.50 \leq 0.80$ मि.मि. | ज |
| | | $> 0.80 \leq 1.20$ मि.मि. | झ |
| | | > 1.20 मि.मि. | ट |
| 6 | 1 | ≤ 600 मि.मि. | 1 |
| | | > 600 मि.मि. ≤ 900 मि.मि. | 2 |
| | | > 900 मि.मि. | 3 |
| 7 | 1 | एज रोलड एजिज / मिल एजिज | द |
| | | ट्रिम्ड एजिज | ध |
| 8 | 1 | ऑयलड | ण |

| क्र.सं. | अंकों की संख्या | विवरण | कोड |
|---------|-----------------|----------------|-----|
| | | ऑयल न किया गया | प |

10. हितबद्ध पक्षकार जांच शुरूआत नोटिस की तारीख से 10 दिन के भीतर पीसीएन कार्य प्रणाली पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

समान वस्तु

11. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत को संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और नियमावली के तहत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

12. आवेदन को घरेलू उत्पादकों की ओर से भारतीय स्टील एसोसिएशन (आवेदक) द्वारा दायर किया गया है। निम्नलिखित आवेदक उत्पादकों ने निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ अपनी क्षति सूचना उपलब्ध कराई है :-

क. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,

ख. जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड

ग. जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

घ. आर्सीलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड

13. आवेदन को (i) टाटा स्टील लिमिटेड और (ii) टाटा स्टील बी एस एल लिमिटेड (भूतपूर्व भूषण स्टील लिमिटेड) द्वारा समर्थन प्राप्त है।
14. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड एवं जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं।
15. एस्सार स्टील इंडिया लि. को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 02.08.2017 के आदेश द्वारा निगमित दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया में शामिल किया गया था। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 द्वारा स्थापित कार्य प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, आर्सीलर मित्तल इंडिया प्रा. लि. एक सफल संकल्प आवेदक बन गया है या 16.12.2019 से इसने कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता अधिग्रहित कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा एक नया निगमन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के परिणामस्वरूप एस्सार स्टील इंडिया लि. का नाम परिवर्तित हो कर दिनांक 08.01.2020 से आर्सीलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी हो गया। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी भारत में निगमित है। यह हॉट रोलड प्रोडक्ट्स (कॉयल और गैर-कॉयल दोनों में) और कोल्ड रोलड प्रोडक्ट्स का घरेलू उत्पादक है और इसकी भारत में महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं और इसके और अधिक विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। मै. निप्पोन स्टील और सुमिटोमो मेटल कॉरपोरेशन, जापान की आर्सीलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमि. में कोई सीधी शेयरधारिता नहीं है किंतु यह बहुत सी मध्यस्थ स्वतंत्र निगमित उद्यमों द्वारा पृथक की गई एक माध्यमिक धारक कंपनी में एक अल्पसंख्यक शेयरधारक है। आर्सीलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमि. ने पी ओ आई के दौरान निप्पोन स्टील और सुमिटोमो मेटल कॉरपोरेशन, जापान से संबद्ध वस्तुएं आयात नहीं की हैं। आर्सीलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लि. एक स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कंपनी है और अपने शेयरधारकों के वैयक्तिक हित को नहीं दर्शाती। घरेलू उत्पादक के रूप में, यह

तथ्य कि यह वर्तमान निर्णायक समीक्षा की मांग करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ एकजुट है, इस बात का प्रमाण है कि यह अन्य घरेलू उत्पादकों से अलग तरीके में कार्य नहीं कर रहा है। आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

16. इसलिए, प्राधिकारी का विचार है कि इस संबंध में भारत में समान वस्तु के उत्पादक के रूप में आर्सिलर मित्तल निप्पोन इंडिया लिमिटेड के मूल चरित्र को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत आर्सिलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी घरेलू उद्योग के पात्र संघटक के रूप में मानते हैं।
17. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी आवेदक उत्पादकों को नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग मानते हैं।
18. यह नोट किया गया है कि आवेदक उत्पादक समर्थकों सहित, कुल घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक भाग के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, और उचित जांच के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) की शर्तों के पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन ऊपर दी गई नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में स्थिति के मापदंड को पूरा करते हैं।

कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

चीन जन.गण.

19. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क)(1) का उद्धरण दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद उत्पादित करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां अभिभावी हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर प्रस्तुत करने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार-चालित हैं तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों की शर्तों में परिकलित किया जाना चाहिए।
20. आवेदक ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तथापि, आवेदक इसके संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका है। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के विभिन्न ग्रेड हैं और इसे बहुत से एच एस कोड के तहत वर्गीकृत किया गया है और इन कारणों से इसके संबंध में सही विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना कठिन हो गया है।
21. इसलिए, आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार “कोई अन्य उचित आधार” के आधार पर निर्धारित किया है। इस संबंध में, आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए निम्नलिखित के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है (क) कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत (ख) घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर खपत मानदंड, परिवर्तन लागत, और एस जी ए लागत, और (ग) उचित लाभ/जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

जापान, कोरिया आर पी और यूक्रेन

22. आवेदक ने दावा किया है कि वे जापान, कोरिया आर.पी. और यूक्रेन में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में समर्थ थे। तदनुसार, जापान, कोरिया आर.पी. और यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य को निम्न के आधार पर निर्धारित किया गया (क) कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, (ख) घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर खपत मानदंड, परिवर्तन लागत और एस जी ए लागत, तथा (ग) उचित लाभ।

23. जांच शुरूआत के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

24. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदावार आयात आकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों, कमीशन/व्यापारी के लाभ और गैर-वापसी योग्य वैट (केवल चीन जन. गण. के लिए) के कारण कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

25. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इसके प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है, जिसके द्वारा यह इंगित होता है कि संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है।

पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

26. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और कीमत, सकारात्मक पाटन मार्जिन, घरेलू उद्योग के निष्पादन, संबद्ध देशों में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताओं, संबद्ध देशों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा लागू उपचारात्मक उपायों की मौजूदगी, अतिशेष क्षमताओं, संभावित व्यापार विपथन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और पी यू सी के आयातों पर भारत द्वारा आधारभूत सीमा शुल्कों में कमी पर विचार करते हुए, शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। प्रथम दृष्टया यह नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और शुल्क के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

27. अतः घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से लिखित साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम के 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की जांच की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

संबद्ध देश

28. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., जापान, कोरिया आर.पी. और यूक्रेन हैं।

जांच की अवधि

29. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) प्रस्तावित की है और क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18 और 2018-19 और पी ओ आई की अवधियां शामिल हैं।
30. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की लंबी अवधि उचित है क्योंकि 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में कोविड-19 के कारण व्यापार प्रभावित हुआ था। कथित पाटित आयातों के कारण उत्पन्न घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति और क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए लंबी अवधि अधिक उचित होगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की 18 महीने की जांच की अवधि (पीओआई) उचित

प्रतीत होती है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016-मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 और जांच की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की अवधियां शामिल होगी।

प्रक्रिया

31. निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण शामिल होगा।
32. संबंधित नियमावली नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

33. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd18-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एम एस वर्ड फॉर्मेट में और डाटा फाइलें एम एस एक्सेल फॉर्मेट में हों।
34. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
35. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
36. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
37. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय-सीमा

38. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd18-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
39. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

40. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
41. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

42. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
43. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
44. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
45. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
46. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
47. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

48. डी जी टी आर की वेबसाइट पर सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची अपलोड की जाएगी। साथ ही उसमें उन सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ईमेल करने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि जारी वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

असहयोग

49. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2021

Case No. AD (SSR)-06/2021

Subject : Initiation of sunset review investigation concerning imports of “Cold Rolled/cold reduced flat steel products of iron or Non-Alloy Steel, or other Alloy Steel, of all width and thickness, not clad, plated or coated” originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP and Ukraine

F. No. 7/6/2021–DGTR.— 1. Indian Steel Association (hereinafter also referred to as the "Applicant" or "Petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited, JSW Steel Coated Products Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant producers") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Cold Rolled/cold reduced flat steel products of iron or Non-Alloy Steel, or other Alloy Steel, of all width and thickness, not clad, plated or coated,” (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP and Ukraine (hereinafter also referred to as "subject countries"). The domestic producers namely, Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited, JSW Steel Coated Products Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (hereinafter referred to as “Applicant producers”) have provided the prescribed information in the Application.

2. The Applicant has alleged that dumping from the subject countries has continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury in case of cessation of duties. The Applicant has requested for extension of duties on imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries was initiated on 11th April 2016 by the Designated Authority. The Designated Authority recommended for imposition of provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 3rd August 2016, which was imposed on 17th August 2016 vide Notification No. 45/2016-Customs (ADD). Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject countries vide final findings Notification No. 14/12/2016-DGAD dated 10th April 2017. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 18/2017-Customs (ADD) dated 12th May 2017. The definitive anti-dumping duty will remain in force till 16th August 2021.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present sunset review investigation is “Cold rolled / cold reduced flat steel products of iron or non-alloy steel, or other alloy steel, of all widths and thickness, not clad, plated or coated.”

The following are excluded from the scope of product under consideration.

- a) Stainless Steel.
- b) High Speed Steel, i.e., alloy steels containing, with or without other elements, at least two of the three elements Molybdenum (Mo), Tungsten (W) and Vanadium (V) with a combined content by weight of 7% or more, 0.6% or more of Carbon and 3 to 6% of Chromium.
- c) Silicon Electrical Steels conforming to Grain Oriented and Non- Grain Oriented Steels i.e. alloy steels containing by weight, at least 0.6% but not more than 6% of Silicon and not more than 0.08% of Carbon. This steel may also contain by weight not more than 1% of Aluminium but no other element in a proportion that would give the steel the characteristics of other alloy steel.
5. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation is the same as in the original investigation.

6. The PUC includes cold rolled / cold reduced flat steel products in coils or not in coils including slit coils or sheets, blanks whether or not annealed or box annealed or batch annealed or continuously annealed or any other annealing process or full hard or partially hard. The product concerned covers cold-rolled / cold-reduced flat steel products conforming to prime or non-prime quality whether or not rolled from 4-high reversible mill, 6-high reversible mill, Sendzimir mill, 20-high cold rolling mill, Pickling Lines and Tandem Cold Rolling Mills (PLTCM), Continuous Annealing Line (CAL) or any other cold rolling / cold reducing processes. These products may be oiled or supplied without oil of any type, standard, specification and grade. These products may be conforming to various qualities of steel including but not limited to full hard, partially hard, commercial quality, drawing, deep drawing, extra deep drawing, interstitial free steel, high strength low alloy steels, advance high strength steels, ultra high strength steels, alloy steels, microalloyed steel, TRIP steel (Transformation Induced Plasticity), tin mill black plates (TMBP), and many more qualities, whether or not vacuum degassed through any vacuum degassing process. These steels may be produced and supplied with or without skin pass / temper rolling, whether or not aluminium killed / non-ageing quality and whether or not containing Boron and / or Titanium and/or Vanadium or any other suitable elements of any level by weight.
7. These steels may find applications spread across various end-usages including but not limited to automotive industry, tractors, bicycles, appliances, furniture, electrical panels, packaging, drums, barrels, general engineering, substrate for coating, color coating galvanizing, metal-coating / plating, tin plate etc. and many more applications.
8. The PUC is classified under Custom Tariff Headings 7209, 7211, 7225 and 7226 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present review investigation.
9. It is noted that the domestic industry has not proposed PCN methodology in the sunset review petition. However, it is noted that in the original investigation, PCN methodology was proposed by the domestic industry, and the Authority determined Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the dumping margin. The PCNs prescribed in the original investigation are given below, and the same is proposed to be used **for the present sunset review.**

| S. No. | No. of Digits | Description | Code |
|--------|---------------|--|------|
| 1 | 1 | CRFH - Cold Rolled Full Hard including Partially Hard | F |
| | | Annealed - Cold Rolled Annealed | A |
| 2 | 1 | "Coil" including slit coil | X |
| | | "Not-In-Coil" including sheets and blanks of various shapes and sizes | Y |
| 3 | 1 | Alloy | L |
| | | Non Alloy | N |
| 4 | 4 | Plain Carbon steels with Carbon \leq 0.15% and maximum UTS \leq 410 MPa - conforming to : a. Commercial quality; b. Drawing / Deep Drawing quality (D/DD) c. Extra Deep Drawing quality (EDD) | Q01Q |
| | | Plain Carbon steels with Carbon \leq 0.06% and maximum UTS \leq 350MPa - conforming to Interstitial Free - Extra Deep Drawing quality (IF-EDD) | Q02Q |
| | | Plain Carbon High Strength steels whether or not Interstitial Free, with UTS \geq 350MPa - IF-HS or HS | Q03Q |
| | | Plain Carbon and / or Micro-alloyed steels of Advanced High Strength Quality (AHSS) with minimum UTS \geq 440MPa | Q04Q |
| | | Micro-alloyed steels of Advanced High Strength Quality (AHSS) with minimum UTS \geq 590MPa | Q05Q |

| S. No. | No. of Digits | Description | Code |
|--------|---------------|---|------|
| | | Micro-alloyed steels of Advanced High Strength Quality (AHSS) with minimum UTS $\geq 780\text{MPa}$ | Q06Q |
| | | Micro-alloyed steels of Advanced High Strength Quality (AHSS) with minimum UTS $\geq 980\text{MPa}$ | Q07Q |
| | | Bake-Hardening Steel with minimum UTS $\geq 370\text{MPa}$ (BH) | Q08Q |
| | | Dual-Phase Steel with minimum-UTS $\geq 370\text{MPa}$ (DP) | Q09Q |
| | | Corrosion Resistant Steel (CORTEN) | Q10Q |
| | | Medium and High Carbon steels with Carbon $>0.15\%$ | Q11Q |
| | | Any other grades / quality | Q12Q |
| 5 | 1 | $\leq 0.50\text{mm}$ | G |
| | | $> 0.50 \leq 0.80\text{mm}$ | H |
| | | $> 0.80 \leq 1.20\text{mm}$ | I |
| | | $> 1.20\text{mm}$ | J |
| 6 | 1 | $\leq 600\text{mm}$ | 1 |
| | | $> 600\text{mm} \leq 900\text{mm}$ | 2 |
| | | $> 900\text{mm}$ | 3 |
| 7 | 1 | As Rolled edges / mill edges | R |
| | | Trimmed edges | S |
| 8 | 1 | Oiled | O |
| | | Uncoiled | U |

10. Interested parties may offer their comments, if any, on the PCN methodology within 10 days from the date of the initiation notice.

Like article

11. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject countries to India. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic industry

12. The application has been filed by Indian Steel Association (Applicant) on behalf of the domestic producers. The following applicant producers have provided their injury information for the purposes of the sunset review investigation:
- Steel Authority of India Limited
 - JSW Steel Limited
 - JSW Steel Coated Products Limited
 - ArcelorMittal Nippon Steel India Limited.
13. The application is supported by (i) Tata Steel Limited and (ii) Tata Steel BSL Limited (erstwhile Bhushan Steel Limited).
14. Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited and JSW Steel Coated Products Limited have neither imported the subject goods from the subject countries nor they are related to any exporter or importer of the subject goods.

15. Essar Steel India Ltd. was admitted to corporate insolvency resolution process by way of an Order dated 02.08.2017 passed by the National Company Law Tribunal, Ahmedabad. Pursuant to the procedure established by the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, ArcelorMittal India Pvt. Ltd. became the successful resolution applicant and with effect from 16.12.2019 took over the entire shareholding of the company. Pursuant to issuance of a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies, the name of Essar Steel India Ltd. was changed to ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd. with effect from 08.01.2020. The Company is incorporated in India under the Companies Act, 1956. It is a domestic producer of Hot Rolled Products (both in coil and not-in coil) and Cold Rolled Products and has significant production capacities in India and is in the process of further expansion. M/s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan has no direct shareholding in ArcelorMittal Nippon Steel India Limited but is a minority stakeholder in an intermediate holding company separated by several intervening independent corporate enterprises. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited has not imported the subject goods from Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan during the POI. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited is an independent, professionally managed company and does not reflect the individual interests of its shareholders. As a domestic producer, the very fact that it has come together with other domestic producers to seek the present sunset review evidences that it is not acting in a manner different from other domestic producers. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited has not imported the subject goods from the subject countries.
16. Therefore, the Authority has considered that the relationship has not affected the basic character of the ArcelorMittal Nippon Steel India Limited as producer of the like product in India. The Authority, therefore, considers ArcelorMittal Nippon Steel India Limited as eligible constituent of domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.
17. As per evidence available on record, the applicant producers account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the applicant producers as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules.
18. It is noted that the Applicant Producers, along with the supporters, account for more than 50% of the total domestic production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant Producers constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

Basis of alleged dumping

Normal value

China PR

19. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- 1 to Rules.
20. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country, price from such a third country to other countries, including India. However, the applicant could not get reliable information regarding the same. The applicant has claimed that PUC has various grades and is classified under multiple HS codes, and because of these reasons it becomes difficult to get accurate reliable information regarding the same.
21. Therefore, the applicant has determined normal value for China PR on the basis of “any other reasonable basis” as per Para 7 of Annexure 1 to the Rules. In this regard, the applicant has claimed the normal value for China PR based on (a) International price of raw material, (b) Consumption norms, conversion costs and SGA costs on the basis of experience of the domestic industry, and (c) a reasonable profit. There is sufficient evidence of normal value to justify initiation of investigation.

Japan, Korea RP and Ukraine

22. The applicant has claimed that they were unable to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in Japan, Korea RP and Ukraine. Accordingly, normal value for Japan, Korea RP and Ukraine has been constructed based on (a) International price of raw material, (b) Consumption norms, conversion costs and SGA costs on the basis of experience of the domestic industry, and (c) a reasonable profit.
23. For the purpose of initiation, the Authority has considered the normal value claimed by the applicant.

Export price

24. The export price for subject goods from the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, commission/trader's profit and non-refundable VAT (only for China PR).

Dumping margin

25. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin determined is not only above de-minimis level but also significant. There is *prima facie* evidence that normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries have continued to be exported at dumped prices, in spite of antidumping duty in force.

Likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury

26. There is *prima facie* evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the volume and price of imports of subject goods from subject countries, positive dumping margin, the performance of the domestic industry, significant unutilized capacities in subject countries, existence of trade remedial measures imposed by other countries against the subject countries, excess capacities, potential trade diversion, price attractiveness of Indian market and reduction of basic custom duties by India on imports of PUC. It is *prima facie* noted that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

Initiation of sunset review investigation

27. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject countries and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Countries

28. The subject countries for the present sunset review investigation are China PR, Japan, Korea RP and Ukraine.

Period of Investigation (POI)

29. Petitioner has proposed the period from 1st April 2019 to 30th September 2020 (18 months) as the period of investigation (POI). The injury investigation period is 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.
30. A longer period of investigation is appropriate in the present sunset review since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the current injury and likelihood of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports. In view of the above, period of investigation (POI) of 18 months from 1st April 2019 to 30th September 2020 is considered appropriate. The injury investigation period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the period of investigation i.e., 1st April 2019 to 30th September 2020.

Procedure

31. The sunset review investigation will undertake likelihood analysis of dumping and injury.
32. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

Submission of Information

33. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd18-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
34. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the

domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

35. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
36. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other parties.
37. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

38. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, ddl8-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per as Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
39. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

40. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
41. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
42. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
43. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
44. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The nonconfidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
45. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
46. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
47. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

48. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

49. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority